का मुकाबला करने में सुरक्षाकर्मियों द्वारा अगर अनजाने में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो उन्हें राहत देने के लिए सरकार उचित क़ानून बनाएगी, एक खतरनाक संकेत है। यह बात उन्होंने पिछले पांच सितम्बर को विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था। आडवाणी ने तो पंजाब में आतंकवाद को कुचलने के नाम पर पुलिस व सुरक्षाबलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले पुलिस जनों पर चल रहे मुकदमों को उठा लेने व उन्हें आम माफी देने तक की बात कह डाली थी। लेकिन इस बयान पर हुई आलोचनाओं के बाद वह इससे मुकर गये कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी।

आडवाणी के इस खुले अभयदान से पंजाब के भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक के.पी.एस.गिल सरीखे लोगों को मनचाही मुराद मिल गयी। गिल उन पुलिस अधिकारियों में से हैं जो पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों व सेना द्वारा आतंकवाद को कुचलने के नाम पर बर्बर अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मानवाधिकार संगठनों को अक्सर खरी-खोटी सुनाते रहते हैं। वह अक्सर इस पर अफसोस जाहिर करते रहते हैं कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नाहक लम्बी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पुलिस को ही वे न्याय की कुर्सी पर बिठा देने की वकालत के जोश और कानून से हाथ बंधे होने की कसमसाहट में एक बार उन्होंने यहां तक कह डाला था कि *'इस नामर्द देश में पैदा क्यूं कर दिया।'* आडवाणी अगर 'अनजाने ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सुरक्षाकर्मियों को राहत दिलाने के लिए उचित कानून' बनवाने में सफल रहे तो के.पी.एस. गिल जैसों को अपनी मर्दानगी दिखाने का भरपूर अवसर मिल जायेगा।

जाहिर है कि इबलीस की औलादों को राज्यसत्ता का भरपूर संरक्षण हासिल है। ऐसे में भला वे अपनी शैतानी हरकतों से क्यूंकर बाज आयेंगे। आने वाले समय में ये हरकतें और बेकाबू होती जायेंगी अगर देश में एक मजबूत जनतांत्रिक अधिकार आन्दोलन नहीं संगठित होगा। जनप्रतिरोध के अलावा इबलीस की औलादों के कहर से बचने का कोई दूसरा उपाय भी नहीं है।

बोलते आंकड़े चीखती सच्चाइयां

देश में बुनियादी आर्थिक "सुधार" कार्यक्रमों को लागू होते एक दशक पूरा हो गया। एक दश पूर्व जुलाई, 1991 में तत्कालीन नरसिंह राव-मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार ने आम बजट के साथ "उदारीकृत" आर्थिक नीतियों का पहला खेप परोसी थी। तब से लेकर अब तक चुनावी वामपंथियों से लेकर लगभग सभी किस्म के रंग-रोगन वाली पार्टियां सत्ता में भागीदारी कर चुकी हैं – चाहे संयुक्त मोर्चा रहा हो अथवा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन। क्या है इन "सुधारों" की सच्चाई, देखते हैं कुछ आंकड़ो की जुबानी –

* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 1999 को प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद देश में 3,06,221 लघु उद्योग और 2,363 निजी मझोले और बड़े उद्योग बंद हो चुके थे। उदारीकरण के दस वर्ष पूरा होते-होते (यानी 2001 में) बंद छोटे-बड़े उद्योगों की संख्या लगभग चार लाख तक पहुंच चुकी है और चार करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छीनी जा चुकी हैं। उदारीकरण के बाद बीमार उद्योगों की संख्या डेढ़ गुने से ऊपर पहुंच चुकी है।

* आर्थिक सर्वेक्षण 2001 के अनुसार 1997 के मुकाबले 2000-2001 तक एक लाख चौवालिस हजार सरकारी नौकरियों और पचास हजार निजी क्षेत्र की नौकरियों में कटौती की जा चुकी है। 1980 में वार्षिक रोजगार वृद्धि दो प्रतिशत थी जो 90 के दशक में महज 0.98 प्रतिशत रह गयी।

* विगत दस वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारों की संख्या में दूने की वृद्धि हो चुकी है और इसमें वृद्धि लगातार जारी है। बेरोजगारों की एक बड़ी आबादी रोजगार कार्यालयों से नाउम्मीद हो चुकी है और वह वहां अपना पंजीकरण नहीं करवाती है। फिर भी जितने लोगों ने वहां पंजीकरण करवाया उनके मुकाबले मिलने वाले रोजगार का प्रतिशत भी गौरतलब है। 1989-90 से 1998-99 के बीच पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में 22.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि रोजगार में महज 6.68 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 1990 में रोजगार कार्यालयों में 3 करोड़ 28 लाख नये लोगों ने पंजीकरण करवाये जिनमें से 2 करोड़ 64 लाख लोगों को रोजगार मिला था जबकि 1999 में 4 करोड़ 2लाख नये पंजीकृत बेरोजगारों में से महज 2 करोड़ 81 लाख लोगों को नौकरियां मिल पायी थीं।

* 1995-96 से 1998-99 के बीच भविष्य निधि योजना से 60 लाख 84 हजार लोगों ने नाता तोड़ लिया है, जिसकी मूल वजह लोगों को नौकरियों से हाथ धोना है।

* 1990-91 में एक डालर का मूल्य 19 रुपये 64 पैसे था जो 1991-92 में दो बार किये गये रुपये के अवमूल्यन के बाद छलांग लगाकर 31 रुपये 23 पैसे के भाव पहुंच गया। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की लाख मशक्कतों और वित्तीय समायोजन के बावजूद इस वक्त (30 अप्रैल, 2001) एक डालर की कीमत 46 रुपये 86 पैसे है और किसी भी वक्त यह 50 रुपये से ऊपर पहुंच सकती है।

* 1991 से 2000 के बीच भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ 1,63,0012 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,29,271 करोड़ रुपये हो गया। आज यह 5 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहा है। आज देश में पैदा होने वाला हर बच्चा दस हजार रुपये कर्ज का बोझ लेकर पैदा हो रहा है।

* विगत दस वर्षों के दौरान जहां नीचे की 70 फीसदी आबादी लगातार जिल्लत और बदहाली की ज़िन्दगी जीने के लिये अभिशप्त होती गयी है लगभग 40 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है वहीं बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था और काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था के कारण ऊपर की 20 फीसदी आबादी के सुख-समृद्धि और ऐशों आराम की ज़िन्दगी (यानी जीवन स्तर) छलांग लगाकर काफी ऊपर चली गयी है। उदारीकरण का लाभ इसी आबादी को मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 1999 के बीच बहुराष्ट्रीय कम्पनी डच-ब्रिटिश यूनीलीवर की भारतीय शाखा हिन्दुस्तान लीवर की आय 1800 करोड़ से बढ़कर 11,400 करोड़ हो गयी, जबकि इसी अवधि में देशी पूंजीपति रिलायंस उद्योग समूह का कारोबार 2,954 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,562 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।